



2026: AHC: 1374

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 41519 सन् 2025

रणवीर सिंह

.....आवेदक

बनाम

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- पवन कुमार कुशवाहा, ठाकुर प्रसाद दुबे

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- आशीष पांडेय

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार कुशवाहा तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष पांडेय के प्राधिकार के अधीन श्री विपुल पांडेय को सुना गया तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक रणवीर सिंह की ओर से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अपराध संख्या 15 सन् 2025 में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, 1985 की धारा 8/18/27A, 29/60, 25 के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण, पुलिस थाना-एन० सी० बी० लखनऊ, जनपद- बदायूँ में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से 1 किलोग्राम 600 ग्राम अफीम बरामद किए जाने का आरोप लगाया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वस्तुतः आवेदक के कब्जे से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः अपराध में उसके मिथ्या रूप से फंसाए जाने जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान वाद में अभियोजन द्वारा एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त अनिल कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 6.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 29749 सन् 2025 में जमानत पर उन्मोचित किया जा चुका है। आवेदक, जो दिनांक 12.7.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, जमानत पर उन्मोचित किए जाने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण के पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है; अतः, आवेदक किसी भी प्रकार की राहत की पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दंड की कठोरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की तार्किक आशंका, सार्वजनिक/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध में संलिप्त आवेदक **रणवीर सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर मुक्त होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक की पहचान, स्थिति तथा निवास के प्रमाण एवं प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाएगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश